भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)

विधानसभा चुनावों की समीक्षा रिपोर्ट

(केन्द्रीय कमेटी की 11-12 जून 2011 को हैदराबाद में हुई बैठक में स्वीकृत)

अप्रैल-मई 2011 में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु एवं केन्द्र शासित प्रदेश पुदुच्चेरी की विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए थे। असम के अपवाद को छोड़कर, बाकी सभी राज्यों में सरकारें बदली हैं। हालांकि अखिल भारतीय स्तर पर कोई एक जैसे रुझान उभरकर नहीं आये हैं।

प्रथमत:, प0 बंगाल में, वाममोर्चे को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इससे देश भर की वामपंथी व प्रगतिशील तबकों को बड़ी निराशा हुई है। तीन दशक के वाममोर्चा शासन के बाद प्रदेश की जनता ने निर्णायक रूप से परिवर्तन को चुना है। यह परिणाम समूचे देश के वामपंथ के लिए एक धक्का है।

केरल में हालांकि एल डी एफ मामूली अंतर से चुनाव हार गया है, लेकिन इसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। यूडीएफ एक प्रतिशत से भी कम के अंतर से चुनाव जीत पाया है। अपनी सरकार के काम के रिकार्ड, भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता की भावनाओं तथा महंगाई को रोक पाने में केन्द्र की यूपीए सरकार की असफलताओं के चलते, एलडीएफ जनता के बड़े हिस्से का समर्थन हासिल कर सका। केरल के चुनाव परिणाम दिखाते हैं कि जनता का बड़ा हिस्सा वामपंथी मंच एवं नीतियों का समर्थन करता है।

तमिलनाडु में भ्रष्टाचार व कुशासन की वजह से डी एम के राज के खिलाफ एक लहर थी। ए आई ए डी एम के और उसके साझीदारों को 85 प्रतिशत सीटें मिली हैं। यहां भी लोगों ने डी एम के - कांग्रेस गठबंधन को, भ्रष्टाचार व महंगाई जैसे, केन्द्र की यूपीए सरकार से सीधे जुड़े मुद्दों के आधार पर खारिज किया है।

पुदुच्चेरी में, परंपरागत रूप से मजबूत कांग्रेस पार्टी में चुनाव के पहले विभाजन हो गया था। ए आई ए डी एम के पार्टी के साथ चुनावी तालमेल करने वाली एन आर कांग्रेस ने यहां चुनाव जीता है।

केवल असम है जहां कांग्रेस को निर्णायक विजय मिली है। पिछले चुनाव के विपरीत इस बार कांग्रेस अकेले बहुमत हासिल करने में कामयाब हुई है। शांति की उत्कंठा व उल्फा के साथ बातचीत से लोगों में बनी उम्मीद तथा विभाजित विपक्ष, कांग्रेस की सफलता के कारणों में हैं।

असम की जीत को छोड़कर कांग्रेस के लिए संतोष करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। तमिलनाडु में इसका सफाया हो गया है, यहां कुल लड़ी 63 सीटों में से यह सिर्फ 5 सीटें जीत पाई है। केरल में, यूडीएफ बड़ी मुश्किल से बहुमत जुटा पाया है। यह भी मुस्लिम लीग के प्रदर्शन के चलते संभव हुआ हुआ है, जिसने 20 सीटें जीती हैं। सी पी आई (एम) की 45 सीटों की तुलना में कांग्रेस मात्र 38 सीटों पर विजय हासिल कर पाई है। प0 बंगाल के चुनाव में मुख्य फायदा तृणमूल कांग्रेस को मिला है, कांग्रेस को उसका छुटभैया सहयोगी रहकर ही संतोष करना पड़ा है।

इन चुनावों में भाजपा की दुर्गति हुई है। इसे असम में, जहां पिछली बार इसकी 10 सीटें थीं, इस बार 5 ही मिली हैं। प0 बंगाल, केरल हो या तमिलनाडु, अन्य किसी भी राज्य में यह एक भी सीट नहीं जीत सकी है।

चुनाव परिणामों और प0 बंगाल में हार के बाद सी पी आई (एम) और वामपंथ को राजनीतिक रूप से बेदम साबित करने के लिए प्रचार की बाढ़ आ गई है। अतीत में प0 बंगाल में पार्टी एवं वामपंथी आंदोलन, अनेक उतार चढ़ावों से गुजरे हैं और हर बार मजबूत होकर निकले हैं। किसी भी सूरत में पार्टी और वामपंथ,

नव-उदारवादी नीतियों के विरुद्ध मजदूर वर्ग व मेहनतकश जनता के संघर्षों को एवं साम्प्रदायिक ताकतों व साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई को रोकने वाले नहीं हैं। इस पराजय से समुचित सबक लेते हुए पार्टी एवं वामपंथ अपनी पूरी शक्ति वामपंथी आंदोलन को दोबारा ताकत प्रदान करने की दिशा में लगायेंगे।

प0 बंगाल

प0 बंगाल के विधानसभा चुनावों में वाममोर्चे को भारी हार का सामना करना पड़ा है और इसके नतीजे में 34 वर्षों से लगातार चला आ रहा वाममोर्चे का शासन खत्म हो गया है। परिवर्तन के नारे पर सवार तृणमूल कांग्रेस नीत गठबंधन ने 227 सीट हासिल कर झाड़ूमार सफलता हासिल की है। वाम मोर्चा सिर्फ 62 सीटों पर जीत हासिल का सका है। वाममोर्चा को 41.12 प्रतिशत वोट मिले हैं; तृणमूल गठबंधन ने 48.54 प्रतिशत वोट पाये हैं और इस तरह 7.42 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है।

इन चुनावों में वाममोर्चे को कुल 1 करोड़ 95 लाख वोट मिले हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव की तुलना में, जब वाममोर्चे ने 1 करोड़ 84 लाख वोट हासिल किए थे, ये वोट 11 लाख अधिक हैं। लोकसभा चुनाव की तुलना में वाममोर्चे के हिस्से आये वोटों में 2.2 प्रतिशत की कमी आई है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन को 2 करोड़ 30 लाख वोट मिले हैं जो 2009 के लोकसभा चुनाव में इसे मिले वोटों से 35 लाख अधिक हैं। 2006 के विधानसभा चुनावों में 1 करोड़ 98 लाख वोट के साथ वाममोर्चे ने 50.18 प्रतिशत मत हासिल किए थे। उसके मुकाबले इन चुनावों में 10 प्रतिशत मतों की गिरावट आयी है, जो इतनी भारी हार के लिए जिम्मेदार है।

19 जिलों में से, केवल तीन-कूच-बिहार, जलपाईगुड़ी एवं उत्तर दिनाजपुर-में ही वाममोर्चे ने तृणमूल गठबंधन से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। इन चुनावों की एक विशेषता बर्द्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया एवं प0 मेदिनीपुर जैसे परंपरागत रूप से वामपंथ के मजबूत जिलों में, तृणमूल कांग्रेस गबठबंधन के वोट हिस्से में हुई बढ़ोतरी है।

ये विधानसभा चुनाव सत्ताधारी वर्गों और साम्राज्यवाद द्वारा मिलकर सी पी आई (एम) एवं वामपंथ को कमजोर करने की सतत कोशिशें किए जाने की परिस्थितियों में हुए थे। ये कोशिशें यूपीए-प्रथम की सरकार के दौर में नव-उदारवादी नीतियों एवं संयुक्त राज्य अमरीका के साथ रणनीतिक गठबंधन के विरोध में, वामपंथ द्वारा निभाई गई भूमिका की वजह से शुरू हुई थीं। जुलाई 2008 में सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद ये कोशिशें और तीव्र हो गईं। सत्ताधारी वर्ग और साम्राज्यवादी ऐजेंसियों ने, देश में वामपंथ के सबसे मजबूत आधार वाले प0 बंगाल में, वामपंथ पर हमले के लिए विभिन्न ताकतों को इकट्ठा करने का काम किया।

ये चुनाव पार्टी एवं वामपंथी कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहे हमलों की पृष्ठभूमि में हुए थे। मई 2009 के लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव पूरे होने तक, 388 वामपंथी कार्यकर्ताओं व समर्थकों की हत्याएं की जा चुकी थीं। जंगलमहल इलाके में तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर माओवादियों ने चुन-चुनकर हत्यायें करने व आतंक बरपा करने का काम किया। कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे पूर्वी-मेदिनीपुर जिले के एक हिस्से में, हमारे लिए चुनाव अभियान तक चलाना मुमकिन नहीं था।

परिणामों से जाहिर है कि 2008 के पंचायत चुनावों में वाममोर्चा के विरुद्ध जो रुझान आंशिक रूप से उजागर हुआ था, 2009 के लोकसभा चुनाव एवं 2010 के नगरपालिका चुनावों में जारी रहा। उसने 2011 के विधानसभा चुनाव में और गति हासिल कर ली। जनता ने निश्चय के साथ परिवर्तन के लिए वोट दिया।

वाम मोर्चा सरकार के लगातार 34 वर्ष लंबे राज के चलते विभिन्न नकारात्मक कारक इकट्ठा हो गए थे, जिन्होंने जनता को परिवर्तन के लिए वोट देने की ओर धकेला। प्राथमिक समीक्षा उन कारणों की ओर इशारा करती है जिनकी वजह से परिवर्तन का यह मानस बना। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(1) हाल के वर्षों में वाममोर्चा सरकार के कामकाज में अनेक कमियां थीं, जिनमें से ज्यादातर कमियों को लोकसभा चुनाव की समीक्षा के वक्त नोट किया गया था। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं अन्य विकास व कल्याणकारी कदमों के मामले में थीं। कुछ कार्यक्रमों व योजनाओं को लागू करने की शुरूआत ही नहीं की गयी थी। बुनियादी सेवाओं व उन्हें प्रदान करने में अक्षमताओं के चलते जनता में असंतोष पनपा।

(2) राजनीतिक स्तर पर, दक्षिणपंथी शक्तियों से लेकर अतिवाम तक समूचे विपक्ष की पूर्ण एकता थी। तृणमूल गठबंधन में कांग्रेस एवं एस यू सी आई शामिल थे। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और वृहत्तर कूच बिहार आंदोलन जैसे संगठन, इस गठबंधन को समर्थन दे रहे थे। तृणमूल-माओवादी गठबंधन सक्रिय था। इस वाम-विरोधी गठबंधन ने पिछली तीन वर्षों में गति पकड़ी और लोगों के एक हिस्से ने इसे वाम-मोर्चा के विकल्प के रूप में देखा।

(3) सिंगूर और नंदीग्राम की घटनाओं ने भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को सामने ला दिया। तृणमूल गठबंधन ने यह भ्रामक प्रचार करके कि वाम मोर्चा सरकार किसानों से उनकी जमीन छीन लेगी, इसका सी पी आई (एम) एवं वाम मोर्चे के खिलाफ कारगर इस्तेमाल किया गया। जैसा कि केन्द्रीय समिति ने लोकसभा चुनावों की समीक्षा मे ंनोट किया था "किसानों के एक हिस्से व पार्टी के बीच फांक करने के लिए, तृणमूल गठबंधन इस मुद्दे का कारगर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है।" इस संबंध में हुई प्रशासनिक व राजनीतिक गलतियां महंगी साबित हुई हैं। इस वादे के बावजूद कि किसानों की सहमति के बिना जमीन नहीं ली जायेगी, इस मुद्दे पर सी पी आई (एम) एवं वाममोर्चे के विरुद्ध चलाए गए अभियान ने ग्रामीण अवाम के बीच पार्टी के समर्थन में आई कमी में योगदान किया। नंदीग्राम की घटनाओं व बाद में हुए गोलीचालन ने, बुद्धिजीवियों एवं मध्यम वर्ग के हिस्सों को हमसे दूर कर दिया।

(4) सांगठनिक पहलू भी एक महत्वपूर्ण कारक है। स्वेच्छाचारिता, नौकरशाहाना रवैये और जनता की बात सुनने से इंकार के प्रकटीकरण से, आम लोगों में पार्टी की छवि को आघात पहुंचा था। "सत्ता पार्टी" होने तथा लंबे समय से सरकार में रहने के नुकसानदेह प्रभाव की वजह से, पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के छोटे से हिस्से में भ्रष्टाचार व गलत कामों की प्रवृत्ति पाये जाने के विरुद्ध भी जनता के बीच असंतोष था। इन सबने चुनाव में पार्टी पर असर डाला।

(5) मजदूर वर्ग एवं शहरी तथा देहाती गरीबों के समर्थन में आई कमी, वर्गीय मुद्दों को लगातार उठाने में हमारी विफलता को इंगित करती है। प्रशासन पर निर्भरता ने पार्टी एवं जनसंगठनों की स्वतंत्र भूमिका को नुकसान पहुंचाया।

(6) नैगम घरानों द्वारा नियंत्रित जन-प्रचार माध्यमों ने योजनाबद्ध तरीके से लगातार वाममोर्चा एवं खासतौर सी पी आई (एम) के खिलाफ दुष्प्रचार का अभियान चलाया। लगातार तीन वर्षो तक चले इस गहन प्रचार ने जनता के कुछ हिस्सों विशेषकर मध्यमवर्गीय तबकों को प्रभावित किया। जनता की वर्ग-आधारित एकता को कमजोर करने के लिए पहचान की राजनीति को प्रोत्साहन दिया गया। इस चुनाव में, जो प0 बंगाल में पहले कभी नहीं देखा गया था, पैसे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। अनेक स्वयंसेवी संगठन व साम्राज्यवादी एजेंसियां, वाममोर्चे के खिलाफ सक्रिय थीं।

लोकसभा चुनाव में लगे धक्कों के बाद, सरकार एवं संगठन के स्तर पर कल्याणकारी कदम उठाने व जनता से रिश्तों को फिर से जोड़ने के कुछ उपाय भी किए गए। मगर सुधार के ये कदम जरूरी असर नहीं छोड़ सके। लोकसभा चुनाव की समीक्षा में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के एक हिस्से के हमसे हुए अलगाव को नोट किया गया था एवं उसके कारणों को संबोधित करने की बात कही गयी थी। बहरहाल मुस्लिमों को ओ बी सी

श्रेणी में शामिल कर रोजगार में आरक्षण देने जैसे कदम, कोई फर्क डालने के लिहाज से काफी देर से उठाये गए।

उत्तरी 24 परगना, हावड़ा, हुबली और वर्द्धमान जैसे मजदूर वर्गीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अपने कमजोर प्रदर्शन के कारणों की हमें पड़ताल करनी चाहिए। निचली इकाइयों की जानकारी के आधार पर संपूर्ण चुनाव समीक्षा हमें इस बात की ज्यादा सही तरीके से पहचान करायेगी कि जनता के किन हिस्सों में, किस हद तक, हमने अपनी जमीन गंवाई है। इस तरह की समीक्षा के आधार पर हमें जनता से रिश्तों की पुर्नबहाली करने तथा संगठन की कमियों से उबरने के लिए, आवश्यक राजनीतिक एवं सांगठनिक कदम उठाने होंगे। संगठन को सुसंबद्धता देने के कदम उठाने होंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक दुरुस्तीकरण का सिलसिला चलाना होगा।

1977 के बाद एक के बाद एक आई 7 वाममोर्चा सरकारों की ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं। इनमें भूमि सुधार है, जिसने 30 लाख किसानों और 15 लाख बर्गादारों (बंटाईदारों) को फायदा पहुंचाया है; विकेन्द्रीकरण व लोकतांत्रिक पंचायत प्रणाली की स्थापना है, जिसने ग्रामीण जनता को स्थानीय प्रशासन व विकास में भागीदारी प्रदान की एवं देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। मेहनती जनता के विभिन्न तबकों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूती के साथ स्थापित किया गया। स्थायित्वपूर्ण धर्मनिरपेक्ष प्रशासन कायमी किया गया, जिसकी पहचान साम्प्रदायिक सौहार्द्र एवं शांति थी।

इन तमाम महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद, वाममोर्चा सरकार पूंजीवादी-सामंती व्यवस्था की सीमाओं में रहकर काम कर रही थी। इन उपलब्धियों के रहते हुए भी नव-उदारवादी व्यवस्था के समग्र चौखटे में काम करने की सीमाएं व मुश्किलें, सामने दिखाई देनी लगी थीं। इस लिहाज से एक और अधिक विस्तृत समीक्षा की जानी चाहिए कि क्या नव-उदारवादी व्यवस्था के दायरे के विकल्प की नीतियों को अमल में लाने के लिए वाममोर्चा सरकार ने पर्याप्त यत्न किए थे।

हालांकि हमें एक बड़ा चुनावी धक्का लगा है, फिर भी यह नोट किया जाना चाहिए कि वाममोर्चा को 1 करोड़ 95 लाख से अधिक वोट मिले हैं जो कुल डाले गए वोटों का 41 प्रतिशत है। यह साबित करता है कि वाम विरोधी ताकतों की आक्रमकता व तमाम प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद, जनता के एक बड़े हिस्से ने सी पी आई (एम) एवं वाम मोर्चे को वोट दिया है। अनेक स्थानों पर, गरीब एवं मेहनतकश पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। इस जन समर्थन के आधार पर हमें खोई हुई जमीन दोबारा हासिल करने की ओर बढ़ना होगा। हमें तीन दशकों के वाम मोर्चा राज में जनता द्वारा कठिनाई से हासिल उपलब्धियों व मेहनतकश जनता के अधिकारों की हिफाजत के लिए, आने वाले संघर्षो की अगली कतार में रहना होगा। हमें केन्द्र की कांग्रेस-तृणमूल गठबंधन सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना होगा। जनता की जिंदगी व हितों की रक्षा के लिए आंदोलन छेड़ने होंगे। हमें वामपंथी पार्टियों की एकता को बरकरार रखना होगा एवं अन्य जनवादी शक्तियों को लामबंद करना होगा।

पार्टी को खासतौर से तीन दशकों के भूमि सुधार एवं पूंजीवादी संबंधों के विकास के कारण वर्गीय संबंधों में आये बदलावों का अध्ययन करना होगा। हमें ग्रामीण धनी तबके के सामने आन के बाद, वर्गीय स्थिति में आये बदलावों की जांच करनी होगी। इसी के साथ नव-उदारवादी नीतियों के असर के चलते मध्यम वर्ग एवं अन्य तबकों में भी बदलाव आये हैं। हमारे काम की बुनियादी वर्गों एवं गरीब तबकों की ओर वर्गीय उन्मुखता का निर्धारण, इसी आधार पर किया जा सकता है।

फौरी हालात में पार्टी एवं वाममोर्चे को बड़े पैमाने पर हमलों का सामना करना पड़ रहा है। नेताओं व कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर हिंसा की जा रही है। अभी तक 14 नेताओं व कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। इनमें से 13 सी पी आई (एम) के हैं और 1 आर एस पी के। इन हमलों में अनेक साथी जख्मी हुए

हैं। महिलाओं के साथ बदसलूकी, बेहुरमती की गई है। अनेक पार्टी कार्यालयों पर हमले कर, तोड़-फोड़ की गई है। कुछ पर कब्जा कर लिया गया है। हमारे हजारों समर्थकों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। दैनिक अखबार ***गणशक्ति*** को निशाना बनाया गया है। इस अखबार को बेचने वालों पर हमले कर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। यूनियनों के कार्यालय दखल कर लिए गए हैं, उन पर कब्जे कर लिए गए हैं। कुछ जगहों पर किसानों पर, उनकी जमीन से उनका अधिकार छीन लेने के लिए, हमले किए गए हैं। कुछ स्थानों पर फसलें लूटी या नष्ट की गई हैं। कालेजों में छात्र संघों को निशाना बनाया जा रहा है।

इस तरह के हमलों से हमें पार्टी एवं जनसंगठनों की रक्षा करनी होगी। जिन कार्यकर्ताओं को हिंसा का निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हिफाजत करनी होगी। हमें वाममोर्चे के साथ मिलकर, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा एवं इस तरह की हिंसा के विरूद्ध जनता के बीच एक बड़ा एवं व्यापक अभियान छेड़ना होगा। प0 बंगाल में पार्टी एवं आंदोलन पर हमले को, देश भर में लोकतंत्र की रक्षा एवं मेहनतकश जनता के अधिकारों का मुद्दा बनाना होगा। केन्द्रीय कमेटी इन कठिन परिस्थितियों में दसियों हजार पार्टी कार्यकर्ताओं व वामपंथी कार्यकर्ताओं के समर्पित काम व निर्भीक भावना की सराहना करती है। उन्हें मौजूदा हालात से उबरने में, समूची पार्टी और वामपंथी व जनतांत्रिक आंदोलनों का पूरा समर्थन व एकजुटता मिलेगी।

केरल

केरल विधानसभा चुनाव में यूडीएफ बहुत थोड़े से अंतर से विजयी हुआ है। यूडीएफ को 72 सीटें मिली हैं। यह बहुमत के लिए जरूरी सीटों से सिर्फ 1 ज्यादा है। एलडीएफ को 68 सीटें मिली हैं जो बहुमत से 3 कम हैं। एलडीएफ ने 44.94 प्रतिशत वोट हासिल किए हैं। ये लोकसभा चुनाव में एलडीएफ को मिले 41.95 प्रतिशत से 3 फीसदी अधिक हैं। यूडीएफ एवं एल डी एफ के बीच अंतर मात्र 0.89 प्रतिशत का है।

राज्य के कुल 14 जिलों में से 8 में एलडीएफ को यूडीएफ की तुलना में अधिक वोट मिले हैं, जबकि 6 जिलों में ही यूडीएफ ने ज्यादा वोट पाये हैं। दोनों के बीच कुल अंतर 1 लाख 55 हजार वोट का है। यूडीएफ ने अकेले मलप्पुरम जिले में 3 लाख 69 हजार वोटों की बढ़त हासिल की है। इसका मतलब यह हुआ कि इस जिले को छोड़कर बाकी केरल में एलडीएफ 2 लाख 14 हजार वोटों से आगे रहा।

ये चुनाव कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार की बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से कलंकित छवि एवं महंगाई रोक पाने में विफलता की, राष्ट्रीय राजनीतिक पृष्ठभूमि में हुए थे। इन दोनों ही मुद्दों ने राज्य में कांग्रेस-नीत गठबंधन पर विपरीत प्रभाव डाला। चुनाव के कुछ ही महीने पहले यूडीएफ के एक पूर्व-मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा सुनाये जाने से केरल में भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुख रूप से आगे आ गया था। एक अन्य पूर्व मंत्री की संलिप्तता वाले आइसक्रीम पार्लर सैक्स कांड में नए खुलासे से, यह मुद्दा भी ताजा हो गया था।

केरल में इन चुनावों की एक महत्वपूर्ण विशेषता जनता के बीच सरकार-विरोधी भावनाओं की अनुपस्थिति थी। एलडीएफ सरकार के जनोन्मुखी विकास एवं व्यापक सामाजिक सुरक्षा के कदमों ने जनता के बीच सराहना हासिल की थी। गरीबी की रेखा के नीचे की श्रेणी से बाहर के परिवारों को भी 2 रुपये किलो चावल देने, मेहनतकश जनता के सभी तबकों की पेंशन में बढ़ोतरी व मछुआरों के कल्याण के लिए कदम, बंद पड़े बागानों को खोलने, परंपरागत उद्योगों के मजदूरों की सहायता, राज्य के सार्वजनिक उद्यमों का मुनाफा पैदा करने वाले संस्थानों के रूप में पुनरोद्धार-इन सभी ने जनता का समर्थन जुटाने में योगदान दिया। एलडीएफ सरकार की ओर से पेश किए गए पिछले बजट में भी अनेक जनहितैषी कदम थे। जनता पर इनका भी सकारात्मक असर पड़ा।

एलडीएफ सरकार के अच्छे काम-काज के अलावा कुछ अन्य कारण भी रहे जिन्होंने हर पांच साल में सरकार के बदलने के चक्र को लगभग समाप्त कर देने की स्थिति लाने में योगदान दिया। इस चुनाव में

एलडीएफ कहीं ज्यादा एकजुट था। लोकसभा चुनाव की तरह इस बार सीटों के बंटवारे के लेकर कोई विवाद नहीं था। पार्टी ने भी एकजुट होकर काम किया। इस बार लोकसभा चुनाव के वक्त जैसे मुद्दे या विवाद नहीं थे।

मुख्यमंत्री के रूप में वी एस अच्युतानंदन द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाये जाने एवं भ्रष्टाचार विरोधी मंच से छेड़े गए उनके अभियान को लोगों के बीच व्यापक समर्थन हासिल हुआ। चुनाव अभियन में इसे बड़ा जनसमर्थन मिला।

लोकसभा चुनाव के वक्त जनता दल (एस) का बहुमत एलडीएफ छोड़ गया था। केरल कांग्रेस (जोसेफ) का बहुमत एवं आई एन एल भी एलडीएफ से अलग हो गए थे। इन पलायनों के बावजूद, एलडीएफ अपनी खोई जमीन को दोबारा हासिल करने व अग्रगति बनाने में सफल रहा।

चुनावों की तैयारी के लिए किए गए सांगठनिक काम ने भी एलडीएफ के लिए समर्थन जुटाने में मदद की। राज्य समिति ने 74 सीटों को जीतने के लिए लक्ष्यबद्ध करते हुए इनमें योजनाबद्ध काम की योजना बनाकर दी। इनमें से 30 वे सीटें थीं जिन्हें एलडीएफ ने लोकसभा व स्थानीय निकाय दोनों में जीता था। 29 वे सीटें थीं जिन्हें इन दोनों में से किसी एक में जीता गया था एवं 15 सीटें वे थीं जिनमें एलडीएफ इन दोनों चुनावों में 5 हजार वोटों से पीछे रहा था। इस योजनाबद्ध काम ने इनमें से अनेक सीटों पर अच्छे प्रदर्शन के साथ परिणाम दिए। एलडीएफ ने 74 लक्ष्यबद्ध सीटों में से 53 पर जीत हासिल की। 15 ऐसी सीटें जीतीं जो इस श्रेणी में शामिल नहीं थीं।

एक दर्ज किए जाने योग्य विशेषता मजदूर वर्ग का एलडीएफ को समर्थन रही। नारियल-रेशा मजदूर, काजू मजदूर, मछुआरों, बागान मजदूरों एवं मजदूर वर्ग के अन्य हिस्सों ने बड़े पैमाने पर पार्टी एवं एलडीएफ उम्मीदवारों को वोट दिए। यह अलेप्पी, इडुक्की और कोल्लम जैसे जिलों में साफ दिखाई दिया। अनुसूचित जाति की 12 सीटों में से 10 एलडीएफ ने जीतीं जबकि वायनाड जिले की दोनों अनुसूचित जाति की सीटें यूडीएफ के पास गईं। यूडीएफ को विभिन्न जाति एवं धार्मिक संगठनों के समर्थन का लाभ मिला। जिस नायर सर्विस सोसायटी (एन एस एस) ने दोनों मोर्चों से समान दूरी रखने का दावा किया था उसने असल में एलडीएफ के खिलाफ काम किया। हालांकि वह सभी जगह इस समुदाय से जुड़े लोगों को प्रभावित नहीं कर पाई। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में इसके अभियान ने एलडीएफ को प्रभावित किया। एस एन डी पी ने भी कमोबेश यूडीएफ उम्मीदवारों के पक्ष में काम किया। यहां भी आमतौर से एझवा अवाम उनकी तरफ नहीं गया। मगर बहुत नजदीकी अंतर के चुनाव में कुछ स्थानों पर हो सकता है इसकी वजह से संतुलन दूसरी तरफ झुका हो।

लोकसभा चुनाव एवं स्थानीय निकायों के चुनावों में क्रिश्चियन चर्च के हिस्से खुले तौर पर एलडीएफ के खिलाफ सामने आये थे। इस कम्युनिस्ट विरोधी अभियान का नेतृत्व रोमन कैथोलिक चर्च ने किया था। इस बार कैथोलिक चर्च संस्थान की ओर से विरोध की कोई खुली अभिव्यक्ति दिखाई नहीं दी। हालांकि कुछ स्थानों पर एलडीएफ के विरोध में वोट डालने का रुझान बना रहा। क्रिश्चियन चर्च का गैर-कैथोलिक हिस्सा एलडीएफ के खिलाफ मैदान में नहीं आया।

मलप्पुरम जिले में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पक्ष में मुस्लिम एकत्रीकरण हुआ था। यहां की 16 सीटों में से एलडीएफ केवल 2 जीत सका। मुस्लिम लीग, अनेक धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों को अपने गिर्द इकट्ठा करने में सफल रही। इसका असर मलप्पुरम जिले के बाहर भी कुछ स्थानों पर महसूस किया गया। पलक्काड जिले की मलप्पुरम से सटी 2-3 सीटों पर एलडीएफ के खिलाफ मुस्लिम एकत्रीकरण हुआ। नतीजे में एलडीएफ को इन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। याद रखना होगा कि 2004 के लोकसभा तथा 2006 के विधानसभा चुनावों में, मलप्पुरम जिले में मुस्लिम आवाम का समर्थन हासिल करने में पार्टी ने प्रगति की थी। इस घटना विकास से सतर्क एवं चिंतित मुस्लिम लीग ने, अपने समर्थन में गिरावट को थामने के लिए अनेक

उपाय किए थे। राज्य कमेटी ने मुस्लिम लीग के गिर्द मुस्लिम एकत्रीकरण का गहनता से परीक्षण करने का निर्णय लिया है। पिछले अनुभव दिखाते हैं कि अपने सतत धर्मनिरपेक्ष एवं साम्राज्य-विरोधी रुख की वजह से मुस्लिम अवाम के बीच व्यापक समर्थन पाने में पार्टी कामयाब रही थी। समीक्षा के बाद हमें मुस्लिम आवाम के बीच काम को आगे बढ़ाने की योजना बनानी होगी।

भाजपा ने इस चुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए सक्रियता से काम किया। पिछले चुनावों के विपरीत जब भाजपा अपने वोट यूडीएफ के लिए स्थानांतरित कर दिया करती थी, इस बार ज्यादातर भाजपा वोट उसके उम्मीदवारों के लिए ही पड़े। कुछ सीटों पर उसके स्थानीय नेताओं ने समझौता कर अपने वोट यूडीएफ उम्मीदवारों के लिए स्थानांतरित भी किए। भाजपा ने इस चुनाव में 6.08 प्रतिशत वोट हासिल किए। 2006 के विधानसभा चुनाव में इसके वोट 4.75 प्रतिशत थे, जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में इसे 6.49 प्रतिशत वोट मिले थे।

जिन सीटों पर हम मामूली अंतर से हारे हैं, उनकी गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि पराजय के कारणों को पता लगाया जा सके। राज्य कमेटी की समीक्षा में कुछ सांगठनिक कमजोरियां सामने आई हैं। यह पता चला है कि कई स्थानों पर ब्रांचें घर-घर जाने का काम नहीं कर रही हैं। सक्रियता का यह बुनियादी, तरीका पार्टी का संदेश जनता तक ले जाने के अलावा लोगों के संपर्क में रहने एवं उनकी राय को सुनने का जरिया भी है। जहां भी यह उपयोग में नहीं लाया जा रहा, वहां इसे फिर से बहाल किया जाना चाहिए।

अधिक महिला प्रत्याशियों को खड़ा करने में विफलता को नोट किया जाना चाहिए। भविष्य में इस उपेक्षा के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा।

राज्य कमेटी ने अपनी समीक्षा में इस चुनाव में संसदवाद के रुझान में वृद्धि को नोट किया है। कुछ नेतृत्वकारी कैडर उम्मीदवार न चुने जाने की वजह से अप्रसन्न थे। कुछ तो पार्टी छोड़ने की हद तक चले गए। कुछ ने उम्मीदवार बनने के लिए अनुचित तरीके अपनाये। कुछ मामलों में कामरेड ने दो टर्म की सीमा का उदाहरण देते हुए, दोबारा चुनाव लड़ने का हक जताया।

संसदीय अवसरवाद की इन अभिव्यक्तियों का मुकाबला किया जाना चाहिए। यह याद रखा जाना चाहिए कि केरल की गुटबाजी की जड़ें इस संसदवाद की बीमारी में ही पाई गई हैं। इस संबंध में दुरुस्तीकरण अभियान को जारी रखा जाना चाहिए।

तमिलनाडु

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में ए आई ए डी एम के और उसके चुनावी सहयोगियों को झाड़ूमार सफलता मिली है। डी एम के गठजोड़ का सफाया हो गया है। ए आई ए डी एम के और उसके चुनावी सहयोगियों ने 203 सीटें जीती हैं, जबकि डी एम के गठबंधन को केवल 31 सीटें मिली हैं। ए आई ए डी एम के और उनके सहयोगियों ने 51.8 प्रतिशत वोट हासिल किए हैं जबकि डी एम के गठबंधन 39.43 प्रतिशत वोट जुटा पाया है। ए आई ए डी एम के गठबंधन के पक्ष में 12.4 प्रतिशत वोट की जबर्दस्त लहर थी।

राज्यों के ये चुनाव भ्रष्टाचार के बड़े घोटालों की पृष्ठभूमि में हुए थे, जिसमें 2-जी स्पैक्ट्रम घोटाले में डी एम के की लिप्तता केन्द्र में थी। ए राजा की गिरफ्तारी, कलइंगर टीवी चैनल की जांच एवं रिश्वत लेने के मामले में कनिमोझी के परिजनों का लपेट में आने के मुद्दों के चलते, डी एम के भ्रष्ट कुशासन के विरुद्ध अभियान आगे-आगे रहा। डी एम के की भागीदारी के चलते यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार ने तमिलनाडु पर सीधा असर डाला। एक अन्य कारक व्यापार, मीडिया और फिल्म उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में करुणानिधि के परिवार का वर्चस्व था। प्रतिद्वंद्वियों को कुचलने व खुद को अमीर बनाने के लिए राज्य मशीनरी के नंगे इस्तेमाल ने, जनता

में रोष पैदा किया। डी एम के सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याण योजनाओं के असर को परिवार-धंधे के गठजोड़ के प्रति जनता के रोष ने नकार दिया।

जरूरत की चीजों की कीमतों में वृद्धि एवं इस मामले में यूपीए सरकार की विफलता ने भी, डीएमके गठजोड़ के विरु द्ध आक्रोष को भड़काया। बिजली कटौती एवं उद्योग व कृषि पर इसके विपरीत प्रभाव, डी एम के के संरक्षण में अपराधों के ताने-बाने का फलना फूलना एवं बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे कारकों ने, डीएमके विरोधी जनादेश में अपना योगदान दिया।

ए आई ए डी एम के की नेत्री सुश्री जयललिता ने इस तीव्र असंतोष को भुनाया और वे डीएमके कुशासन का अंत देखना चाहने वालों के एकत्रीकरण के केन्द्र के रूप में उभरकर आईं।

ए आई ए डी एम के द्वारा बनाई गई चुनावी समझदारी मजबूत एवं कारगर थी। इसका एक मुख्य कारण डीएमडीके का शामिल होना था। इस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 10 प्रतिशत वोट हासिल किये थे। विजयकांत के नेतृत्व वाले डीएमडीके के साथ नौजवानों की काफी मजबूत तादाद है।

नगदी एवं अन्य वस्तुओं के बांटने के जरिये चुनावों में धन बल का इस्तेमाल करने के मामले में तमिलनाडु कुख्यात हो गया है। इस बार अवैध धन के प्रवाह को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ कारगर कदम उठाये। करीब 60 करोड़ रुपये जब्त किए गए। हालांकि इन कदमों के बावजूद कई स्थानों पर पैसा बांटा गया, मगर लोग चूंकि धन बल के असर में आये बिना वोट डालने के लिए संकल्पबद्ध थे, इसका असर काफी सीमित रहा।

हालांकि ए आई ए डी एम के और उसके सहयोगियों के पक्ष में आम रुझान था, सरकारी कर्मचारियों व शिक्षकों के बीच ऐसा नहीं था। ए आई ए डी एम के की पिछली सरकार के सरकारी कर्मचारियों के विक्टीमाइजेशन के रिकार्ड को देखते हुए, कर्मचारियों व शिक्षकों के एक बड़े हिस्से ने डीएमके गठबंधन को वोट दिया।

पार्टी का प्रदर्शन

सी पी आई (एम) ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 10 सीटों पर उसने जीत हासिल की। पलायम कोट्टाई सीट हम सिर्फ 605 वोटों से हार गए। पार्टी डिंडीगुल, पैरंबूर, मदुरै साउथ, हरूर एवं तिरुपुर साउथ जैसी अपनी पहले जीती सीटें अच्छे बहुमत से पुन: जीतने में सफल रही। किलवेलुर सीट पार्टी ने 724 वोट से जीती है। यह पार्टी का परंपरागत रूप से मजबूत इलाका है। राज्य समिति ने उन कारणों की जांच का निर्णय लिया है जिनके चलते इस सीट पर हम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाये। कन्याकुमारी जिले की विलावानकोड की सिटिंग सीट पर पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले 23789 वोट से हार मिली है। इस जिले में ए आई ए डी एम के अधिक मजबूत नहीं है। ऐसा लगता है कि यहां ईसाई वोटों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में चला गया। चूंकि जिले में पार्टी परंपरागत रूप से मजबूत है इसलिए कुछ हिस्सों के समर्थन में आई कमी चिंता की बात है। राज्य कमेटी को चुनाव के रुझान व संगठन की स्थिति के बारे में और आगे जांच करनी चाहिए।

राज्य कमेटी की समीक्षा में नोट किया गया है कि पार्टी सदस्यता का एक खासा हिस्सा, जिन 12 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा वहां भी, चुनाव अभियान में सक्रिय नहीं था। कुछ मामलों में तो पार्टी सदस्यों का केवल 50 प्रतिशत हिस्सा ही सक्रिय था। यह पार्टी सदस्यता के नीचले राजनीतिक एवं सांगठनिक स्तर का संकेत है। पार्टी सदस्यता को सक्रिय करने व पार्टी संगठन को सुसंबद्ध बनाने के कदम उठाये जाने चाहिए।

सी पी आई (एम) की 10 सीटों के अलावा सी पी आई ने 9 तथा फारवर्ड ब्लाक ने 1 सीट जीती है। 20 वामपंथी विधायकों के इस धड़े को राज्य में वामपंथी राजनीति व वैकल्पिक नीतियों को लोगों के बीच में ले जाने में मददगार होना चाहिए।

असम

असम विधानसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेस की स्पष्ट जीत के रूप में आये हैं। कांग्रेस ने 78 सीटें जीतकर 39.38 प्रतिशत वोट हासिल किए हैं। यह 2006 के चुनाव की तुलना में 8 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी दिखाता है। भाजपा और असम गण परिषद (एजीपी) का सफाया हो गया है। एजीपी को 10 सीटें मिली हैं। इसका मत प्रतिशत 20.4 प्रतिशत से घटकर 16.3 प्रतिशत पर आ गया है। भाजपा ने केवल 5 सीटें जीती हैं और इसकी ताकत पिछली विधानसभा के मुकाबले आधी रह गई है।

इन चुनावों की महत्वपूर्ण विशेषता, अल्पसंख्यक आधारित पार्टी ए आई यू डी एफ की ताकत का बढ़ना है। इसने पिछली बार जीती 10 सीटों की तुलना में इस बार 18 सीटें जीती हैं। इसने अपना मत प्रतिशत भी 3.56 प्रतिशत बढ़ाया है। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) ने भी 12 सीटें जीत कर अपनी ताकत बढ़ाई है। बीपीएफ सरकार में साझीदार था, मगर इसने चुनाव अलग रहकर लड़ा था।

एक भी सीट न जीत पाने की वजह से सी पी आई (एम) एवं वामपंथी पार्टियों को धक्का पहुंचा है। पार्टी, सरभोग एवं रंगिया की अपनी दोनों सिटिंग सीट हार गई। इन दोनों क्षेत्रों में पार्टी क्रमश: चौथे एवं तीसरे स्थान पर आई है। सिर्फ सोणितपुर जिले की सूतिया सीट पर 32341 वोट पाकर पार्टी उम्मीदवार दूसरे स्थान पर आयी है। पार्टी ने 17 सीट लड़कर कुल 1.13 प्रतिशत वोट हासिल किए हैं। सी पी आई अपनी इकलौती सीट भी हार गई। राज्य कमेटी की आरंभिक समीक्षा के अनुसार इस चुनावी धक्के का मुख्य कारण पार्टी संगठन में आई कमजोरी तथा जनसंगठनों व जनकार्यवाहियों का विस्तार न हो पाना है। हमें इसकी भी जांच करनी चाहिए कि नस्ल एवं समुदाय के आधार पर लामबंदी के विकसित होते रुझान ने हमारे जनाधार को प्रभावित तो नहीं किया है। परिणामों की विशेषताओं में से एक ए आई यू डी एफ एवं बोडो पार्टी, बीपीएफ की ताकत में बढ़ोतरी है।

पुन: एकीकृत होने के बावजूद एजीपी एकजुट नहीं थी। समूचे विपक्ष के महागठबंधन की पैरवी करने के साथ-साथ इसने भाजपा के साथ समझदारी बनाने के संदिग्ध दांवपेंच भी अपनाये। जनता ने इन अवसरवादी नीतियों को ठुकरा दिया। कांग्रेस को उल्फा के साथ बातचीत की शुरूआत से उपजी शांति की उम्मीदों का लाभ मिला है। "राज्य में शांति एवं विकास" के इसके नारे को सकारात्मक रिस्पांस मिला है। पिछले 2 वर्षों में गरीबों के लिए सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी कदमों की घोषणाएं भी की थीं। इसके साथ चुनाव में बड़े पैमाने पर खर्च किए गए धन एवं विरोधी पार्टियों के बीच वोटों के बंटवारे ने भी, कांग्रेस को फायदा पहुंचाया।

निष्कर्ष

हाल के विधानसभा चुनावों में वाममोर्चे की हार के साथ 1977 से शुरू हुए एक दौर का अंत हो गया है। पिछले तीन दशकों में प0 बंगाल में वाममोर्चा सरकार की मौजूदगी देश भर के वामपंथी एवं लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए शक्ति का स्त्रोत थी। प0 बंगाल व केरल में वाम नेतृत्व की सरकारों के न रहने तथा संसद में वामपंथ की घटी शक्ति से बदली राजनीतिक स्थिति का, कांग्रेस-नीत सरकार नवउदारवादी नीतियों को और तेजी से लागू करने एवं जनता की जिंदगी पर हमले आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करना चाहेगी। वाम मोर्चे की सरकारों की अनुपस्थिति में केन्द्र, राज्यों को रौंदने की कोशिश करेगा। लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले की प्रवृत्ति में भी बढ़त हो सकती है। ऐसी स्थिति में हमें सतर्क रहते हुए ऐसे नीतिगत हमलों का प्रतिरोध करते हुए जनता के अधिकारों की हिफाजत करनी होगी। विजयवाड़ा में हुई केन्द्रीय कमेटी की विस्तारित बैठक

में नवउदार नीतियों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखते हुए, इन नीतियों से प्रभावित लोगों के संघर्षों को छेड़ने का आह्वान किया गया था। पार्टी को साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखनी होगी। हमें अमरीकापरस्त नीतियों का विरोध करना होगा। पार्टी को बुनियादी वर्गों में काम एवं वाम जनवादी शक्तियों की एकता बनाने के लिए अनथक श्रम करना होगा।

इन चुनाव परिणामों ने एक बार फिर तीन मजबूत राज्यों के बाहर पार्टी के निर्माण व विकास के महत्व को रेखांकित किया है।

हमें प0 बंगाल में पार्टी एवं वाममोर्चे के खिलाफ छेड़ी गई हिंसा व आतंक की मुहिम के खिलाफ देश भर की जनतांत्रिक शक्तियों व आम जनता की राय को लामबंद करना होगा।

चुनाव समीक्षा की रिपोर्टिंग के साथ-साथ राज्य कमेटियां पार्टी के अंदर राजनीतिक-सांगठनिक अभियान संगठित करने का कार्यक्रम तैयार करें। अधिकांश पार्टी सदस्य, 1977 के बाद से, तब से हैं जब लगातार प0 बंगाल में वाममोर्चा सरकार रही है। ऐसी सरकार के न रहने से कुछ राजनीतिक भ्रम एवं वैचारिक प्रश्न खड़े हो सकते हैं। पार्टी के अंदर, सही कार्यक्रमात्मक परिप्रेक्ष्य के साथ वामपंथी नेतृत्व वाली राज्य सरकारों की भूमिका की व्याख्या की जानी चाहिए। हमें यह दृढ़ता से दोहराना होगा कि किसी राज्य सरकार के न रहने या चुनावी हार से, पार्टी की बुनियादी समझदारी एवं वर्गीय व जन-संघर्षों पर असर नहीं पड़ेगा।

हमें दुरुस्तीकरण अभियान जारी रखना होगा। इससे मौजूदा परिस्थितियों में सही राजनीतिक-सांगठनिक दिशा लेने में पार्टी सदस्यों व कमेटियों को मदद मिलेगी।

मौजूदा परिस्थिति का सामना करने के लिए समूची पार्टी को एकजुट होकर बढ़ना होगा। हमें अपनी कमजोरियों से उबरने, आंदोलन को गति देने एवं आगे बढ़ने के संकल्प के साथ जनता के बीच जाना चाहिए।

समीक्षा रिपोर्ट का परिशिष्ट

पश्चिम बंगाल

सीटों की स्थिति

वाममोर्चा		तृणमूल-कांग्रेस		अन्य
सी पी आई (एम)	40	टीएम सी	184	5
फारवर्ड ब्लाक	11	कांग्रेस	42	
आर एस पी	7	एसयूसीआई	1	
सी पी आई	2			
सपा	1			
डीएसपी	1			
कुल	62		227	5

वोट प्रतिशत

	2006 विधानसभा	2009 लोकसभा	2011 विधानसभा

लेफ्ट फ्रंट	50.18	43.28	41.17
टीएमसी–कांग्रेस		45.69	48.46
टीएमसी	26.64		
कांग्रेस	14.71		
बीजेपी	1.93	6.15	4.04

केरल

सीटों की स्थिति

एलडीएफ		यूडीएफ	
सी पी आई (एम)	45+2 (निर्दलीय)	कांग्रेस	38
सी पी आई	13	मुस्लिम लीग	20
जनता दल (से)	4	एसजे(डी)	2
एनसीपी	2	केसी(एम)	9
आरएसपी	2	केसी(जे)	1
		केआर एसपी(बी)	1
		केसी(बी)	1
कुल	68		72

वोट प्रतिशत

	2006 विधानसभा	2009 लोकसभा	2011 विधानसभा
एलडीएफ	48.63	41.95	44.94
यूडीएफ	42.98	47.82	45.83
बीजेपी	4.75	6.49	6.05

तमिलनाडु

सीटों की स्थिति

एआईएडीएमके गठबंधन		डीएमके गठबंधन	
पाटी	सीटें जीतीं	सीटें जीतीं	
एआईएडीएमके	150	डीएमके	23
डीएमडीके	29	कांग्रेस	5
सीपीआई(एम)	10	पीएमके	3
सीपीआई	9		
एमएमके	2		

पुथिया तमिलगम	2	
फारवर्ड ब्लाक	1	
कुल	203	31

असम

सीटों की स्थिति एवं वोट प्रतिशत

पार्टी	सीटें जीतीं	वोट प्रतिशत
कांग्रेस	78	39.38
एआईयूडीएफ	18	12.58
बीपीएफ	12	
एजीपी	10	16.3
बीजेपी	5	11.46
एआईटीसी	1	
सीपीआई(एम)	0	1.13
सीपीआई	0	0.52
अन्य	2	
कुल	126	